NT>

Title: Need to provide reservation to the people living below poverty line.

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सूचना के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विाय पर सरकार का ध्यान आकर्ति कर रहा हूं और सरकार से मांग भी कर रहा हूं। देश में दो वर्ग हैं, एक आरक्षित है और एक अनारक्षित है।

जब से देश आजाद हुआ, देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। उन्होंने गरीबों के बारे में विचार करके इस देश में आरक्षण दिया। मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि वह आरक्षण जारी रहे। मेरा एक निवेदन यह है कि इस देश के अंदर एक वर्ग अनारक्षित है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है और गरीब है। लम्बे समय से वह गरीब है। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। अनारक्षित वर्ग से मेरा मतलब यह है कि वह हिन्दू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ऊंची जाति का भी हो सकता है। वह वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण धीरे-धीरे सामाजिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी कमजोर होता जा रहा है और नीचे जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार की नीति आम आदमी के सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने की है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की विामता पैदा हो रही है। धीरे-धीरे हमारे समाज में यह एक नया वर्ग तैयार होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। धीरे-धीरे उसका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर भी नीचे जाता जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अनारक्षित वर्ग के हित के लिए, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार विशेा सुविधा देगी और उनको भी आरक्षण देगी। इस पर समूचा सदन भी सहमत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : मैं इससे इत्तिफाक करता हूं। जवाहर लाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने आरक्षण नहीं दिया था। मंडल कमीशन की संस्तुतियों को सबसे पहले जनता दल की सरकार ने इस देश में स्वीकार करके आरक्षण दिया था। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा का विाय नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह : इस देश में 52 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है।â€¦ (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी : ये किसी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना भी नहीं जानते। मेरी मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। मुझे विश्वास है कि समूचा सदन, हर पार्टी के लोग इससे सहमत होंगे। विभिन्न प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था है, तो मेरा यह कहना है कि केन्द्र इसको क्यों नहीं स्वीकार करती।